श्री सभापति: रिकार्ड तो सब जगह बनता है, अब वह सही बनता है या गलत बनता है, यह दूसरी बात है। आजकल तो रिकार्ड मॉडर्नाइज हो रहा है।

श्री जुएल उराम: सर, आदिवासी ज्यादातर जंगल और दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं। इसलिए जमीन उनके नाम नहीं होती है, उनके दखल में होती है। इस संबंध में सरकार की ओर से बार-बार राज्य सरकार को बताया गया है कि उनके नाम में जमीन के पट्टे होने चाहिए, उसका रेगुलराइजेशन होना चाहिए। अब जमीन नहीं है, उसके लिए हम ने दो-चार सरकार को डिमांड की है कि हम सरकार के पैसे से जमीन खरीद कर देंगे। महोदय, केरल और कर्नाटक को उसके लिए स्वीकृति भी दी है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, क्वैश्चन यह नहीं है, वह यह पूछ रही हैं कि जो जमीन आदिवासियों के नाम पर अलाट होती है, उसका रेगुलराइजेशन नहीं होता, उस के पट्टे नहीं मिलते, उसकी खातेदारी उन को नहीं मिलती।

श्री जुएल उराम: अगर ऐसा स्पेसिफिक केस बताएं तो हम देखेंगे।

* 523. [The questioner (Shri Ghulam Nabi Azad) was absent. For answer *vide* page 54-55 *infra.]*

* 524. [The questioner (Shri Matilal Sarkar) was absent. For answer *vide* page 55-57 *infra*]

Scheme for development of existing export infrastructure of Gujarat

*525. PROF ALKA BALRAM KSHATRIYA : Will the Ministrer of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether there is a scheme for development of the existing export infrastructure of Gujarat;

(b) if so, the details and the cost of the scheme;

(c) the Central aid or contribution released therefor; and

(d) the progress made in implementation of said scheme?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Department of Commerce has a scheme called "Assistance to State Governments for Development of Infrastructure for

Export and Allied Activities (ASIDE)". Under the scheme funds are allocated to State Governments for development of export-related infrastructure. Rs. 322.88 crores was allocated for the scheme in 2002-2003.

(c) and (d) Rs. 14 crores was released to the State Government of Gujarat in 2002-2003 under the scheme. The State Government of Gujarat had identified and sanctioned 2 projects at the total cost of Rs. 182 crores under this scheme.

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : सर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि गुजरात के अंदर मौजूदा निर्यात ढांचे के लिए विकास की कौन-कौन सी योजना है और उस स्कीम के लिए कितना खर्चा किया गया है? इसका आंसर मंत्री जी ने नहीं दिया है।

श्री अरुण जेटली : सभापति जी, विभिन्न एक्सपोर्ट के कार्यक्रमों के समर्थन के लिए केन्द्र की योजनाएं हैं जिसमें एक Critical Infrastructure Balancing Scheme है। इस के तहत 3 करोड़ रुपया गुजरात सरकार को सैंक्शन किया गया है और 1 करोड़ रिलीज हो चुका है। सर, इस के अतिरिक्त इस में ASIDE Scheme (Assistance to State Governments for Development of Infrastructure for Export and Allied Activities) का जिक्र है जिसमें 14 करोड़ रुपए स्टेट के शेयर में रिलीज हो चुका है और 10.63 करोड़ केन्द्र के शेयर में रिलीज हो चुका है। सर, तीसरी योजना केन्द्र की एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क की है जिसके तहत 8.2 करोड़ रुपया रिलीज हो चुका है।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : वह योजना कौन-कौन सी है और गुजरात सरकार ने कौन से दो प्रोजेक्ट रखे हैं?

श्री अरुण जेटली : सभापति जी, केन्द्र की ओर से जो ग्रांट्स दी गयी हैं उस में Kandla SEZ के संबंध में काफी ग्रांट्स इस में से दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त Saregram Industrial Estate है जिसे गुजरात इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन बना रहा है, उस के संबंध में भी केन्द्र की ओर से ग्रांट्स दी गयी है और तीसरे प्रोजेक्ट Marine Disposal of Effluents के संबंध में जो राज्य की योजना, उस के लिए भी असिस्टेंस दी जा रही है।

श्री लेखराज बचानी : माननीय सभापति जी, आप ने 322.88 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूर किए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस के लिए गुजरात सरकार ने कितने पैसे मांगे हैं और गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन है, उस ने क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक्सपोर्ट के संबंध में कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स भेजे हैं और पैसे मांगे हैं?

श्री अरुण जेटली : सभापति जी, यह 322 करोड़ रुपए केवल ASIDE स्कीम के तहत है और जैसा कि मैंने जिक्र किया उस स्कीम के तहत 14 करोड़ रुपए गुजरात सरकार को सैंक्शन

किया जा चुका है। इस के अतिरिक्त जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स हैं, उन का अभी मैं उत्तर दे चुका हूं। गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क्स या एक्सपोर्ट प्रमोशन जोंस के संबंध में जो केन्द्र की गाइडलाइंस हैं, उस के तहत जो भी रिक्वैस्ट्स आई हैं, उन के डिटेल्स भी मैं अभी दे चुका हूं कि कितनी-कितनी रकम उनमें दी गयी है।

* 526. [The questioner (Dr. Vijay Mallya) was absent. For answer *vide* page 52-54 *infra*.]

* 527. [The questioner (Shri S. Agniraj) was absent. For answer *vide* page 58-59 *infra*.]

States for Metro Railway Projects

*528. SHRI K. RAMA MOHANA RAO : Will the MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION be pleased to state :

(a) whether many States have evinced interest in launching Metro Railway Projects in their cities to solve commuters' problem as has been the case in Delhi;

(b) the States interested to have Metro Railway;

(c) whether Government propose to help the States in laying Metro Railway; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION(SHRI ANANTH KUMAR) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Government of Karnataka has commissioned a Detailed Project Report by Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC) for Bangalore Metro Phase-I. The draft Detailed Project Report has been submitted to the Government of Karnataka recently. The Government of Andhra Pradesh has commissioned Delhi Metro Rail Corporation Ltd. for preparing a Detailed Project Report for Hyderabad Metro. Also, the Government of Maharashtra has informed that it is considering a proposal to entrust a study for a metro project in the city to DMRC.

(c) and (d) The State Governments concerned have to formulate project proposals for implementing the Metro Railway in their States. The